



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032020-218578  
CG-DL-E-09032020-218578

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 905]  
No. 905]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2020

का. आ. 1009(अ).—इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा वर्णित भारत गणराज्य की सरकार और ब्रूनेई दारुस्सलाम की सरकार के बीच करों के संग्रहण में सूचना और सहायता के आदान-प्रदान के लिए तारीख 28 फरवरी, 2019 को एक करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) पर हस्ताक्षर किए गए थे;

और उक्त करार 30 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त हुआ जो उक्त करार के अनुच्छेद 12 के अनुसार, उक्त करार को प्रवृत्तन में लाने के लिए संबंधित विधियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने की अधिसूचनाओं के पश्चात् तीसवां दिन था;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि इससे यथाउपबद्ध उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में प्रभावी होंगे।

**भारत गणराज्य की सरकार  
तथा  
ब्रूनेई दारुस्सलाम के  
महामहिम सुल्तान और यांग डि-पेटुआन  
की सरकार  
के बीच  
करों के संग्रहण में सूचनाओं और सहायता के आदान-प्रदान पर करार**

भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्रूनेई दारुस्सलाम के महामहिम सुल्तान और यांग डि-पेटुआन की सरकार, करों के संग्रहण में सूचनाओं और सहायता के आदान-प्रदान को सुगम बनाने की इच्छुक होकर, इस प्रकार सहमत हुई हैं:

**अनुच्छेद 1**

**करार का उद्देश्य और क्षेत्र**

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु व्यवहार्य रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचनाओं में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए व्यवहार्य रूप से सुसंगत हो। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा और अनुच्छेद 8 में दिए गए तरीके में इसको गोपनीय माना जाएगा। सक्षम प्राधिकारी कर दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता भी देंगे। प्रार्थित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे, जहां तक कि वे सूचनाओं के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डालें अथवा उसे विलम्बित न करें।

**अनुच्छेद 2**

**क्षेत्राधिकार**

संविदाकारी पक्ष ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

**अनुच्छेद 3**

**शामिल कर**

1. वे कर, जो इस करार के अध्ययन हैं:
  - (क) ब्रूनेई दारुस्सलाम के मामले में, ब्रूनेई दारुस्सलाम की सरकार द्वारा अधिरोपित या अभिशासित सभी कर;
  - (ख) भारत के मामले में केन्द्र सरकार अथवा राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाये गये प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के कर इस पद्धति पर ध्यान दिये बिना कि वे किस तरह वसूले गये हैं।
2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगा। यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए पर्याप्त रूप से इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगा यदि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार सहमत होते हैं। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान में और संबंधित सूचना एकत्र करने तथा संग्रहण वाले उपायों के संबंध में किन्हीं

महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्षकार की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हों, एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

#### अनुच्छेद 4

#### परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए:

- (क) “ब्रूनेई दारुस्सलाम” पद से अभिप्रेत है—ब्रूनेई दारुस्सलाम का राज्यक्षेत्र जिसमें इसका प्रादेशिक समुद्र, ऐसे राज्यक्षेत्र के ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तक विस्तृत जिस पर इसकी प्रभुसत्ता है, तथा इसके प्रादेशिक समुद्र से परे समुद्री क्षेत्र, समुद्री सतह एवं अधोभूमि सहित, जिसे ब्रूनेई दारुस्सलाम के कानूनों के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र माना गया है अथवा इसके बाद माना जाएगा, जिस पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार यह अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार एवं क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, शामिल हैं;
- (ख) “भारत” पद से अभिप्रेत है—भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, तथा क्षेत्राधिकार हैं;
- (ग) “संविदाकारी पक्ष” पद से तात्पर्य ब्रूनेई दारुस्सलाम अथवा भारत, जैसा भी संदर्भ अपेक्षित हो, से है;
- (घ) “सक्षम प्राधिकारी” पद से तात्पर्य है
  - i. ब्रूनेई दारुस्सलाम के मामले में, वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;
  - ii. भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ङ) “व्यक्ति” पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षकारों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;
- (च) “कम्पनी” पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;
- (छ) “सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी” से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर “जनता द्वारा” क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;
- (ज) “शेयरों का प्रमुख वर्ग” से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;

- (झ) “मान्यता-प्राप्त शेयर बाज़ार” पद से तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाज़ार, बॉम्बे शेयर बाज़ार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई अन्य शेयर बाज़ार, तथा संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत किसी अन्य शेयर बाज़ार से है;
- (ञ) “सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना” से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है, भले ही उसका कानूनी रूप कुछ भी हो;
- (ट) “सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना” से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते ऐसी निधि अथवा योजना में यूनितों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनितों, शेयरों अथवा अन्य हितों को “जनता द्वारा” सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;
- (ठ) “कर” से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;
- (ड) “प्रार्थी पक्ष” से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है, जिसने प्रार्थित पक्ष से कर के संग्रहण में सूचना या सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;
- (ढ) “प्रार्थित पक्ष” से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है, जिससे कर के संग्रहण में सूचना या सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है;
- (ण) “सूचना एकत्र करने वाले उपाय” पद से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है, जो किसी संविदाकारी पक्ष को प्रार्थित जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;
- (त) “संग्रहण के उपायों में सहायता” पद से तात्पर्य संविदाकारी पक्ष के घरेलू कानून में दिए गए उन कानूनों तथा प्रशासनिक अथवा न्यायिक प्रक्रियाओं से है, जो संविदाकारी पक्ष को अनुरोधित कर दावे के संग्रहण एवं प्रेषण के लिए सक्षम बनाते हैं: और
- (थ) “सूचना” पद से तात्पर्य किसी तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद-11 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है।

### अनुच्छेद 5

#### अनुरोध पर सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. अनुरोध करने पर प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद-1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता खुद अपने कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण

जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह प्रार्थित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण प्रार्थित पक्ष के क्षेत्राधिकार में घटित होता है।

2. यदि प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि प्रार्थित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाध्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से, अनुरोध पर निम्नलिखित को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार हो:

(क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना;

(ख) कंपनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, "एन्स्टालटेन" और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद-2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व शृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचनाएं; तथा ऐसी सत्ताओं के बारे में समकक्ष सूचनाएं जो न तो न्यासी हैं और न ही फाउंडेशन ही हैं।

5. यह करार संविदाकारी पक्षों पर सार्वजनिक व्यापार वाली कंपनियों या सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों या योजनाओं की स्वामित्व संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने या उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं डालता, जब तक कि ऐसी सूचनाएं बिना गैर-समानुपातिक कठिनाई उत्पन्न किए प्राप्त की जा सकती हों।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए इस करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं लिखित में उपलब्ध कराएंगे:

(क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

(ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;

(ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्रार्थित पक्ष से प्राप्त करना चाहता है;

(घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

(ङ) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना प्रार्थित पक्ष के पास है अथवा प्रार्थित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

- (च) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है; और
- (छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, प्रार्थी पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना प्रार्थी पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो प्रार्थी पक्ष का सक्षम प्राधिकारी प्रार्थी पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा और यह कि यह इस करार के अनुरूप है;
- (ज) यह विवरण देते हुए कि प्रार्थी पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

7. प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा:

- (क) प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा;
- (ख) यदि प्रार्थित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा इसकी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रार्थी पक्ष को सूचित करेगा।

### अनुच्छेद 5क

#### सूचना का स्वतः आदान प्रदान

मामलों की श्रेणियों के सम्बंध में और उन प्रक्रियाओं के अनुसार जो संविदाकारी पक्ष पारस्परिक सहमति से निर्धारित करेंगे, संविदाकारी पक्ष अनुच्छेद 1 में संदर्भित प्रयोजनों के लिए स्वतः सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

### अनुच्छेद 6

#### विदेश में कर जांच

1. प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर, प्रार्थित पक्ष प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को प्रार्थित पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है जो घरेलू कानूनों के अन्तर्गत अनुमत सीमा तक है ताकि वैयक्तिक अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से वैयक्तिक का साक्षात्कार लिया जा सके तथा रिकार्डों की जांच की जा सके। प्रार्थी पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा।
2. प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, प्रार्थित पक्ष, प्रार्थी पक्ष के प्रतिनिधियों को प्रार्थित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है।
3. यदि पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो प्रार्थित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए प्रार्थित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में प्रार्थी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय, जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

### अनुच्छेद 7

#### सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. किसी संविदाकारी पक्ष को ऐसी सूचना प्राप्त करने या उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं होगी, जिसे दूसरा संविदाकारी पक्ष अपने स्वयं के कर कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के प्रयोजन से अपने स्वयं के कानूनों के तहत प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। संविदाकारी पक्ष का सक्षम प्राधिकारी सहायता करने से मना कर सकता है, जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप न किया गया हो।
2. इस करार के प्रावधान किसी संविदाकारी पक्ष पर ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करने की बाध्यता अधिरोपित नहीं करेंगे जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रकट होती हो। उपरोक्त के बावजूद भी, अनुच्छेद 5, पैरा 4 में संदर्भित सूचनाओं के प्रकार को केवल इसलिए गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया नहीं समझा जाएगा क्योंकि यह उस पैराग्राफ में मापदण्डों को पूरा करती है।
3. इस करार के प्रावधान किसी संविदाकारी पक्ष पर सूचनाएं प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की बाध्यता अधिरोपित नहीं करेंगे, जो किसी ग्राहक तथा अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत वैध प्रतिनिधि के बीच गोपनीय संप्रेषण को व्यक्त करेगा जहां ऐसे संप्रेषण:
  - (क) कानूनी परामर्श मांगने या उपलब्ध करने के प्रयोजनों हेतु प्रस्तुत किए गए हैं; अथवा
  - (ख) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं।
4. कोई संविदाकारी पक्ष सूचना हेतु किसी अनुरोध को ठुकरा सकता है, यदि सूचना को प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।
5. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।
6. कोई संविदाकारी पक्ष सूचना हेतु किसी अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है, यदि सूचना के लिए अनुरोध दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के कर कानून के ऐसे उपबंध को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिक के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे संविदाकारी पक्ष के एक राष्ट्रिक की तुलना में भेदभाव करता है।

### अनुच्छेद 8

#### गोपनीयता

इस करार के तहत किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त किसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा तथा वह सूचना केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को दी जा सकती है, जो संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार में इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के निर्धारण अथवा संग्रहण, उनसे संबंधित प्रवर्तन या अभियोजन, या उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हों। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन से करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। यह सूचना, सूचना उपलब्ध करा रहे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकारी को प्रकट नहीं की जा सकती।



### अनुच्छेद 8 क

#### कर दावों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी पक्ष, अपने संबंधित कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक, कर दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "कर दावा" का तात्पर्य निम्नलिखित करों के संबंध में किसी धनराशि के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली की लागत अथवा ऐसी राशि के संरक्षण के संबंध में बकाया धनराशि है:

(क) ब्रूनेई दारुस्सलाम के मामले में,

- (i) आयकर अधिनियम (Cap. 35) के तहत अधिरोपित आयकर; और
- (ii) आयकर (पेट्रोलियम) अधिनियम (Cap. 119) के तहत अधिरोपित पेट्रोलियम लाभकर;

(ख) भारत के मामले में,

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिरोपित आयकर (उस पर किसी अधिभार सहित);
- (ii) काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम, 2015 के तहत अधिरोपित कर; और

(iii) धन कर अधिनियम, 1957 के तहत अधिरोपित धन कर।

3. जब किसी संविदाकारी पक्ष का कर दावा उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय हो और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय हो जो उस समय उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस कर दावे को उस पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस कर दावे को उस दूसरे पक्ष द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य उसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार वसूल किया जाएगा, मानो वह कर दावा उस दूसरे पक्ष का कर दावा था।

4. जब किसी संविदाकारी पक्ष का कर दावा ऐसा दावा है जिसके संबंध में वह पक्ष, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस कर दावे को उस पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा पक्ष उस कर दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि वह कर दावा उस दूसरे पक्ष का कर दावा हो, भले ही जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, तो वह कर दावा प्रथमोल्लिखित पक्ष में प्रवर्तनीय न हो अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय हो जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. जब कोई संविदाकारी पक्ष अपने कानून के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर दावा किए जाने से पहले उसकी आस्तियों पर रोक लगाकर संरक्षण का उपाय करता है, तो प्रथम संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी उस संविदाकारी पक्ष में अपने कानूनी प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति की आस्तियों पर रोक लगाने के उपाय करेंगे।

6. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के बावजूद, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजन से किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कोई कर दावा, उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे उसकी प्रकृति के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी कर दावे के प्रयोजन से कोई प्राथमिकता नहीं दी



जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजन से किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए कर दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत उस कर दावे पर कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी।

7. किसी संविदाकारी पक्ष के कर दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस पक्ष के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा संबंधित कर दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित पक्ष को प्रेषित करने से पहले संबंधित कर दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

(क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित पक्ष का कोई कर दावा जो उस पक्ष के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस पक्ष के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित पक्ष के कर दावे जिसके संबंध में वह पक्ष अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है;

प्रथमोल्लिखित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे पक्ष के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित पक्ष अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

9. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी पक्ष पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस पक्ष के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।

## अनुच्छेद 9

### लागतें

1. जब तक कि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हों, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को प्रार्थित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्यधीन, सहयोग देने में उपगत असाधारण लागतों को, यदि वे 500 यूएस डालर से अधिक हो जाती हैं, प्रार्थी पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 यूएस डालर से अधिक होने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी, पहले ही, यह निर्धारित करने के लिए एक-दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे कि क्या प्रार्थी पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के संबंध में समय-समय पर परामर्श करेंगे।

4. सामान्य लागतों में आंतरिक प्रशासनिक लागतें, कुछ गौण बाह्य लागतें और अतिरिक्त व्यय शामिल हैं जो प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु अनुरोधों की समीक्षा करने और उनका उत्तर देने के लिए प्रार्थित पक्ष द्वारा व्यय की

गई हों। सहायता उपलब्ध कराने में उपगत असाधारण लागतों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं हैं:

- (क) प्रार्थित पक्ष की ओर से दस्तावेजों के प्रतिलिपिकरण हेतु तीसरे पक्षों द्वारा प्रभारित उचित शुल्क;
- (ख) व्याख्याताओं, अनुवादकों अथवा अन्य मान्य विशेषज्ञों को रखने के लिए उपयुक्त लागतें;
- (ग) प्रार्थी पक्ष को दस्तावेज़ देने के लिए उपयुक्त लागतें;
- (घ) सूचना हेतु एक विशिष्ट अनुरोध के संबंध में प्रार्थित पक्ष की मुकदमेबाजी संबंधी उपयुक्त लागतें; और
- (ङ) बयान अथवा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लागतें।

### अनुच्छेद 10

#### कार्यान्वयन के विधान

संविदाकारी पक्ष इस करार की शर्तों का अनुपालन करने और उन्हें लागू करने के लिए जरूरी कोई कानून बना सकते हैं।

### अनुच्छेद 11

#### पारस्परिक करार की विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार को लागू करने अथवा इसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे।
2. पैराग्राफ-1 में संदर्भित करारों के अलावा, संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5, 5क, 6 तथा 8 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर परस्पर सहमत हो सकते हैं।
3. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे।

### अनुच्छेद 12

#### प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्षकार इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं की पूर्ति के बारे में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख के तीसवें दिन लागू होगा और उसके बाद से तत्काल प्रभावी होगा।
3. इस करार के सभी उपबंध 01 जनवरी 2017 को अथवा इसके बाद प्रारम्भ होने वाली कराधीन अवधियों के लिए अनुच्छेद 5क में प्रत्याशित सूचनाओं के स्वतः आदान-प्रदान के सम्बंध में, अथवा जहां कोई कराधीन अवधि नहीं है, 01 जनवरी को अथवा इसके बाद उत्पन्न करें के सभी प्रभारों पर लागू होंगे।

### अनुच्छेद-13

#### समापन

1. यह करार अनिश्चित समय तक प्रभावी बना रहेगा, लेकिन कोई भी संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष को यह करार लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद राजनैयिक चैनलों के माध्यम से इसके समापन की लिखित नोटिस दे सकता है।

2. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर इस करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. इस करार के किसी समापन के बावजूद, दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार के अन्तर्गत प्राप्त की गई किसी सूचना के बारे में अनुच्छेद 8 के उपबंधों से बंधे रहेंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में 28 फरवरी 2019 तारीख को मलय, हिन्दी और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

श्री प्रमोद चंद्र मोदी

अध्यक्ष

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वित्त मंत्रालय

ब्रुनेई दारुस्सलाम के महामहिम सुल्तान और यांग डि-  
पेर्टुआन की सरकार के लिए

दातो पादुका हाजी साइडक बिन अली

राजदूत असाधारण

और प्लेनिपोटेन्सियरी

ब्रुनेई दारुस्सलाम

[अधिसूचना सं.14/2020/ फा. सं. 503/2/2012-एफटीडी- II]

रश्मि रंजन दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2020

**S.O. 1009(E).**—Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Brunei Darussalam for the exchange of information and assistance in collection with respect of taxes (hereinafter referred to as the said Agreement) as set out in the annexure to this notification, was signed at New Delhi, India on the 28<sup>th</sup> day of February, 2019;

And whereas, the said Agreement entered into force on the 30<sup>th</sup> January, 2020 being the thirtieth day after the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for bringing into force the said Agreement, in accordance with Article 12 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Agreement, as annexed hereto, shall have effect in the Union of India.

## ANNEXURE

### AGREEMENT

#### BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

#### AND

THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI  
DARUSSALAM

FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION AND ASSISTANCE IN COLLECTION WITH RESPECT  
TO TAXES

**The Government of the Republic of India and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, desiring to facilitate the exchange of information and assistance in collection with respect to taxes, have agreed as follows:**

## **Article 1**

### **Object and Scope of the Agreement**

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The competent authorities shall also lend assistance to each other in the collection of tax claims. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

## **Article 2**

### **Jurisdiction**

A Contracting Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

## **Article 3**

### **Taxes Covered**

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
  - (a) in the case of Brunei Darussalam, all taxes imposed or administered by the Government of Brunei Darussalam;
  - (b) in the case of India, taxes of every kind and description imposed by the Central Government or the Governments of political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures and assistance in collection measures which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

## **Article 4**

### **Definitions**

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
  - (a) the term “Brunei Darussalam” means the territory of Brunei Darussalam including its territorial sea, extending to the airspace above such territory, over which it exercises sovereignty, and the maritime area beyond its territorial sea, including sea-bed and subsoil, which has been or may hereafter be designated under the laws of Brunei Darussalam as an area over which it exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law;
  - (b) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
  - (c) the term “Contracting Party” means Brunei Darussalam or India as the context requires;
  - (d) the term “competent authority” means
    - (i) in the case of Brunei Darussalam, the Minister of Finance or his authorized representative;

- (ii) in the case of India, the Finance Minister, Government of India, or his authorized representative;
- (e) the term “person” includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;
- (f) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (g) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- (h) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- (i) the term “recognised stock exchange” means the National Stock Exchange of India, the Bombay Stock Exchange, any other stock exchange recognised by the Securities and Exchange Board of India, and any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;
- (j) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;
- (k) the term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- (l) the term “tax” means any tax to which this Agreement applies;
- (m) the term “requesting Party” means the Contracting Party requesting information or submitting a request for assistance in collection of tax to the requested Party;
- (n) the term “requested Party” means the Contracting Party requested to provide information or assistance in collection of tax;
- (o) the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
- (p) the term “assistance in collection measures” means laws and administrative or judicial procedures as provided by the domestic law of a Contracting Party that enable the Contracting Party to collect and remit the requested tax claim; and
- (q) the term “information” means any fact, statement, document or record in whatever form.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 11 of this Agreement, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

## Article 5

### Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering

measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority, for the purposes specified in Article 1 of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:

- (a) information held by banks, other financial institutions, and any person, acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;
- (b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment funds or schemes, trusts, foundations, “Anstalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and equivalent information in case of entities that are neither trusts nor foundations.

5. This Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under this Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
- (b) the period for which the information is requested;
- (c) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party;
- (d) the tax purpose for which the information is sought;
- (e) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
- (f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information;
- (g) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- (h) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

7. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

- (a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.
- (b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

**Article 5A****Automatic Exchange of Information**

With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall determine by mutual agreement, the Contracting Parties shall automatically exchange information for the purposes referred to in Article 1.

**Article 6****Tax Examinations Abroad**

1. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

**Article 7****Possibility of Declining a Request for Information**

1. A Contracting Party shall not be required to obtain or provide information that the other Contracting Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of a Contracting Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

- (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or
- (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. A Contracting Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (*ordre public*).

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. A Contracting Party may decline a request for information if the information is requested by the other Contracting Party to administer or enforce a provision of the tax law of that other Contracting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the first-mentioned Contracting Party as compared with a national of the other Contracting Party in the same circumstances.



**Article 8****Confidentiality**

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the Contracting Party providing the information.

**Article 8A****Assistance in the Collection of Tax Claims**

1. The Contracting Parties shall, to the extent permitted by their respective domestic law, lend assistance to each other in the collection of tax claims.

2. The term "tax claim" as used in this Article means any amount owed in respect of the following taxes imposed by the Contracting Parties, together with interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount:

- (a) in the case of Brunei Darussalam,
  - (i) income tax imposed under Income Tax Act (Cap. 35); and
  - (ii) petroleum profits tax imposed under Income Tax (Petroleum) Act (Cap. 119);
- (b) in the case of India,
  - (i) income tax (including any surcharge thereon) imposed under the Income Tax Act, 1961;
  - (ii) tax imposed under The Black Money (Undisclosed Foreign Income And Assets) and Imposition of Tax Act, 2015; and
  - (iii) wealth tax imposed under Wealth Tax Act, 1957.

3. When a tax claim of a Contracting Party is enforceable under the laws of that Party and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Party, prevent its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that Party, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting Party. That tax claim shall be collected by that other Party in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the tax claim were a tax claim of that other Party.

4. When a tax claim of a Contracting Party is a claim in respect of which that Party may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that Party, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting Party. That other Party shall take measures of conservancy in respect of that tax claim in accordance with the provisions of its laws as if the tax claim were a tax claim of that other Party even if, at the time when such measures are applied, the tax claim is not enforceable in the first-mentioned Party or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. When a Contracting Party, under its law, takes interim measures of conservancy by freezing of assets before a tax claim is raised against a person, the competent authority of the other Contracting Party if requested by the competent authority of the first-mentioned Contracting Party shall take measures for freezing the assets of that person in that Contracting Party in accordance with the provisions of its law.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a tax claim accepted by a Contracting Party for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a tax claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a tax claim accepted by a Contracting Party for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that tax claim under the laws of the other Contracting Party.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a tax claim of a Contracting Party shall only be brought before the courts or administrative bodies of that Party. Nothing in this Article shall be

construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting Party.

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting Party under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting Party has collected and remitted the relevant tax claim to the first-mentioned Party, the relevant tax claim ceases to be:

- (a) in the case of a request under paragraph 3, a tax claim of the first-mentioned Party that is enforceable under the laws of that Party and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Party, prevent its collection, or
- (b) in the case of a request under paragraph 4, a tax claim of the first-mentioned Party in respect of which that Party may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection,

the competent authority of the first-mentioned Party shall promptly notify the competent authority of the other Party of that fact and, at the option of the other Party, the first-mentioned Party shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting Party;
- (b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
- (c) to provide assistance if the other Contracting Party has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- (d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Party is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting Party.

## Article 9

### Costs

1. Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and subject to the provisions of this Article, extraordinary costs incurred in providing assistance shall, if they exceed 500 US dollars, be borne by the requesting Party.

2. The competent authorities will consult each other, in advance, in any particular case where extraordinary costs are likely to exceed 500 US dollars to determine whether the requesting Party will continue to pursue the request and bear the cost.

3. The competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article.

4. Ordinary costs include internal administration costs, any minor external costs and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to requests submitted by the requesting Party. Examples of extraordinary costs incurred in providing assistance include, but are not limited to the following:

- (a) reasonable fees charged by third parties for copying documents on behalf of the requested Party;
- (b) reasonable costs of engaging interpreters, translators or other agreed experts;
- (c) reasonable costs of conveying documents to the requesting Party;
- (d) reasonable litigation costs of the requested Party in relation to a specific request for information; and
- (e) reasonable costs for obtaining depositions or testimony.

## Article 10

### Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.

**Article 11****Mutual Agreement Procedure**

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 5A, 6 and 8A of this Agreement.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

**Article 12****Entry into Force**

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective law for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and shall thereupon have effect forthwith.
3. The provisions of this Agreement shall have effect with respect to the automatic exchange of information foreseen in Article 5A for taxable periods beginning on or after 1 January 2017, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after 1 January 2017.

**Article 13****Termination**

1. This Agreement shall continue in effect indefinitely, but either of the Contracting Party may, after the expiration of three years from the date of its entry into force, give to the other Contracting Party, through the diplomatic channel, written notice of termination.
2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the provisions of this Agreement.
3. Notwithstanding any termination of this Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi this 28<sup>th</sup> day of February 2019, each in the Malay, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA**

MR. PRAMOD CHANDRA MODY  
CHAIRMAN  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES  
MINISTRY OF FINANCE

**FOR THE GOVERNMENT OF  
HIS MAJESTY THE SULTAN  
AND YANG DI-PERTUAN OF  
BRUNEI DARUSSALAM**

DATO PADUKA HAJI SIDEK BIN ALI  
AMBASSADOR EXTRAORDINARY  
AND PLENIPOTENTIARY  
BRUNEI DARUSSALAM

[Notification No. 14/2020 F.No.503/02/2012-FTD-II]

RASMI RANJAN DAS, Jt. Secy.